action accordingly. On the basis of the preliminary investigation, the Food Corporation of India has placed under suspension one District Manager and six Assistant Managers.

Capacity of FCI Godowns in Gujarat

484. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI ATEL:
SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the allocation and present capacity of the FCI godowns in the State of Gujarat; and

(b) the number of offices and godowns proposed to be opened in the State during the current and next two years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANS PRASAD SINGH): (a) The monthly allocation of foodgrains under TPDS for Gujarat State is 67.5 thousand tonnes. As on 31.5.1997, the Food Corporation of India was having storage capacity of 9.82 lakh tonnes.

(b) At present, there is no proposal with the Government to set up new offices. There is adequate storage capacity available with Food Corporation of India.

उत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों में अनाज की भारी कमी

485. **श्रीमती मालती शर्मा** :
श्री राजनाथ सिंह :
श्री जयन्त कुमार मल्होत्रा :

क्या **खाध और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले चार महीनों से उत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों में अनाज की भारी कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मंत्री की उत्तर प्रदेश क्षेत्रों की यात्रा के दौरान आश्वासन दिया गया था कि इन क्षेत्रों के लिए अनाज की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कमी न हो; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और अनाज की सुविधा उपलब्ध कब तक करा दी जाएगी?

खाध तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को खाधान्नों का मासिक आवंटन उस राज्य के लिए समग्र रूप से किया जाता है और आगे विभिन्न क्षेत्रों/जिलों के बीच उप आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । जून, 1997 से चावल और गेंहू का आवंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फार्मूले पर किया जाता है और पहली जून, 1997 से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो गई है । लाक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उत्तर प्रदेश को किया गया 15.37 लाख टन प्रति वर्ष का आवंटन 1996-97 मे किए गए 12.50 लाख टन उठान से लगभग 3 लाख टन अधिक है ।

राज्य सरकारों द्वारा किए गए उप आवंटनों के अनुसार उत्तर प्रदेश के पहाडी जिलों के लिए खाधान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाध निगम सभी प्रयास कर रहा है । मार्च, 1997 से जून, 1997 तक की अवधि के दौरान केवल अल्मोड़ा जिले में खाधान्नों के पर्याप्त स्टाक का संचलन नही किया जा सका क्योंकि परिवहन ठेका बेस डिपुओं से स्टाक उठाने में असफल रहा था ।

(ग) जी, नही । माननीय प्रधान मंत्री जी ने 21.6.1997 को पतनगर दौरे के दौरान मात्र इतना कहा था कि राज्य सरकार को पेश आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

Import of Wheat of Inferior Quality

486. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of the wheat imported in 1997, quantity thereof, the amount spent thereon, the country from which it was imported and the time when it reached India;